महापौर ने इंदौर की पहचान को किया मटियामेट

सरकारी हत्याओं को लेकर न्याय यात्रा में सभी आमंत्रित - पटवारी

इंदौर, 9 जनवरी. सरकारी हत्याओं को लेकर न्याय यात्रा निकाली जा रही है. शहर की जनसुरक्षा और सहायता के लिए सभी वर्ग, राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन से आग्रह है कि वे न्याय यात्रा में शामिल हो.

महापौर ने इंदौर की पहचान को मटियामेट कर दिया . कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए. यह बात शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से कही है. इंदौर प्रेस क्लब में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्यप्रदेश प्रभारी एवं एआईसीसी महासचिव हरीश चौधरी ने शुक्रवार पत्रकारों से चर्चा की. पत्रकारों को विषय की जानकारी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा त्रासदी में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इंदौर को भाजपा ने क्या दिया? संगठित रूप में हत्याओं और प्रशासन और निगम की लापरवाही के कारण हत्या हुई है. पटवारी ने सवाल किया कि इंदौर में कुएं में धंसने से 36 मौत, चूहे कुतरने से बच्चों को मौत, आग लगने से बच्चों के मौत और अब भागीरथपुरा में जहरीले पानी में 20 से ज्यादा लोगों के मौत के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की गई . सरकार बताएं? किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई आज तक. नगर निगम , सांसद , विधानसभा चुनाव में इंदौर की जनता ने भाजपा को भरोसा दिया. भाजपा ने इंदौर को क्या दिया? 2082 करोड़ रुपए की नल जल और मल योजना की सौगात के साथ 20 लोगों की मौत का पुरस्कार. आपने कहा ,महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की पहचान को मटियामेट कर दिया. भाजपा की परिषद में जहर का पानी पीकर लोग मर रहे है.

भाजपा ने मजदूरी का अधिकार छीना - चौधरी

देश की सर्वश्रेष्ठ मनरेगा योजना को भाजपा ने समाप्त कर दिया . भाजपा ने देश के गांवों में मजदूरी का अधिकार छीन कर प्रचार प्रसार से जी राम जी योजना का महिमा मंडन किया जा रहा है. राम जी के नाम पर मजदूर के अधिकार हनन करना , इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है. उक्त बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी ने पत्रकारों से कही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने गांवों में 100 का रोजगार दिया जा रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश से कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मनरेगा बंद कर दी है. प्रचार प्रसार द्वारा मजदूरों का अधिकार छीन कर झूठा नई योजना का महिमा मंडन किया जा रहा है. देश में पहले राजस्थान में 150 दिन मजदूरी का अवसर मिलता था. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में एक परिवार को 42 दिन रोजगार दिया. राजस्थान में 62 दिन रहा है. भाजपा सरकार कह रही है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था, जांच कर किसी को दंडित किया क्या ? भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके दोषी आप है.

नियुक्तियों में नियमों का नहीं हुआ पालन

हाइकोर्ट ने सभी लॉ ऑफीसर्स से मांगा जवाब

जबलपुर, 9 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में नियम का पालन क्यों नहीं किया गया.

एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय के अलावा सभी लॉ ऑफीसर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए यह याचिका दायर कर की गई है.

मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा. वहीं मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके जैन की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई है. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता पारितोष त्रिवेदी ने पक्ष रखा. न्यायालय को बताया गया कि महाधिवक्ता कार्यालय में कुल 157 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर 25 दिसंबर को सूची जारी की गई है. उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और पक्षपातपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है.

अधिसूचना में कहा गया था कि सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की प्रेक्टिस की योग्यता निर्धारित है. इसके उलट कई शासकीय अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी प्रेक्टिस 10 साल से बहुत कम है. यह दलील भी दी गई कि एक पद पर नियुक्ति के लिए तीन नाम भेजने का प्रावधान था. इसके उलट विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं बताई गई थी. इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था. मांग की गई कि पूरी सूची निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाये. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

ट्रेनों में पर्स, मोबाइल व आभूषण चुराने वाले चोर गिरफ्तार

10 मोबाइल, आभूषण सहित 3 लाख का माल बरामद

नीमच, 9 जनवरी. जीआरपी नीमच ने चलती ट्रेनों में लेडीज पर्स, मोबाइल तथा सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

आरोपियों में राहुल देवड़ा 26 वर्ष निवासी खड़पालिया तथा दशरथ वर्मा 19 वर्ष निवासी नापाखेड़ा जिला मंदसौर शामिल हैं. रेल यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा को लेकर जीआरपी नीमच टीम ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपी नीमच, मंदसौर, मल्हारगढ़, पिपलियामंडी, चित्तौडगढ़ एवं रतलाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों में सक्रिय थे. गिरोह के सदस्य ट्रेन में यात्रियों की नींद लगने का फायदा उठाते थे. ट्रेन में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. ऐसे में होता यह था कि जिनका सामान चोरी होता था उन्हें चोरी होने का पता काफी देर से चलता था.नीमच थाना प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कन्हैयालाल भाटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उक्त दोनों आरोपियों की 3 अपराधों एवं एक अन्य मामले में संलिप्तता सामने आई है.

बाघिन ने शवकों के साथ डाला डेरा

चारों की सुरक्षा में लगी वन विभाग की टीम, अर्लट जारी

छिंदवाड़ा, 9 जनवरी. वन विभाग इन दिनों वन्यप्राणियों की गणना का कार्य कर रहा है. यह कार्य रोजाना ही अल सुबह से शुरू हो जाता है.

जहां वनकर्मी कई किलोमीटर दूर तक चल वन्यप्राणियों के साक्ष्य एकत्र करते है . शुक्रवार के दिन भी वन अमला तामिया के सतपुड़ा के घने जंगलों में वन्यप्राणियों की गणना कर रहा था. तभी नाकेदार और उसके अन्य साथियों को तामिया रेंज के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास घने जंगल में बाघिन अपने तीन शावकों के साथ विचरण करते हुए नजर आई. जिसके बाद तत्काल स्टाफ ने इसकी सूचना वन अधिकारियों को दी. मौके पर पहुंचकर वन अमले ने निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है. दरअसल जिस जगह बाघिन की चहलकदमी नजर आई , वह स्थान आबादी क्षेत्र का बताया जा रहा है. जिसके बाद विभाग ने इस स्थान पर वन विभाग की एक टीम को तैनात कर दिया है. बता दे कि तामिया से लगे सतपुड़ा के घने जंगलों में वन्यप्राणियों का मूवेंट लगातार बढ़ता जा रहा है. इसे मिलाकर अब तामिया रेंज में दो से तीन स्थानों पर तेंदुआ व बाघिन की उपस्थिति देखी जा रही है.

सरकारी राशि गबन करने पर 5 निलंबित

इंदौर. शिक्षा विभाग के बीइओ कार्यालय में 2 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया था. उक्त राशि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने निजी खातों में जमा कर गबन किया, जिसको भोपाल ऑडिट विभाग ने पकड़ा था. कलेक्टर शिवम वर्मा ने संयुक्त संचालक लेखा को जांच अधिकारी नियुक्त किया था. लेखा अधिकारी ने आज उक्त गबन के मामले में जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी. जांच रिपोर्ट ले आधार पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिक्षा विभाग बीईओ कार्यकाल में पदस्थ दिनेश पंवार, मेघना चार्ल्स, भृत्य सिद्धार्थ जोशी, राहुल अहिरे और अतुल त्रिवेदी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं.

एक नजर में

कांग्रेसियों ने किया जमकर प्रदर्शन

जबलपुर, 9 जनवरी. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रांझी खमरिया द्वारा कैंट विधायक अशोक रोहाणी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. यह विरोध इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई 17 लोगों की मौत और इस गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाने वाले पत्रकार का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया. इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा देने की अपील की. प्रदर्शन के दौरान नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, रांझी खमरिया ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष वत्स, राजेश यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा,जग्गू विश्वकर्मा, निर्मल जैन,संजू सिंह सौरभ यादव, आदित्य मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही.

संपत्तिकर वसूलने कुर्की करने पहुंची टीम

रीवा, 9 जनवरी. निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम रीवा की राजस्व टीम ने संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम सूचना के बाद भी भुगतान न करने पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा. इसी क्रम में बड़े बकायादारों के विरुद्ध अंतिम सूचना के पश्चात भी भुगतान न होने पर निगम द्वारा मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. वसूली अभियान को तेज करते हुए आज जोन क्रमांक 02 में 4 स्थानों पर नगर निगम की टीम कुर्की की कार्यवाही हेतु पहुंची, जिसमें सभी बकायादारों द्वारा मौके पर राशि जमा की. जोन क्रमांक 02 में कुर्की की कार्यवाही के दौरान कुसुम सिंह बकाया राशि रू. 54759, इसी प्रकार संतोष पटेल बकाया राशि रू. 68013, अभिमान सिंह बकाया राशि रू. 99239, रामवती मिश्रा बकाया राशि रू. 70284 मौके पर नगर निगम कोष में जमा कराई. इस दौरान नगर निगम उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, अतिक्रमण प्रभारी एवं उपराजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे.

शाजापुर में कोर कमेटी की बैठक में महिला नेत्री रो पड़ी

शाजापुर, 9 जनवरी. ये सियासत की कोर कमेटी है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होती है.

कुछ ऐसा ही आलम बीती रात भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में देखने को मिला, जहां नेताओं के आपसी मनमुटाव को लेकर एक महिला नेत्री की आंखों में उस समय आंसू आ गए, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी. इसके अलावा बैठक में और भी बहस के मुद्दे रहे. कोर कमेटी की बैठक में नजारा कुछ इस तरह का था कि भाजपा में सबकुछ उतना सहज नहीं है, जितना नजर आता है.

गौरतलब है कि शाजापुर जिला भाजपा कोर कमेटी की बैठक बीती रात एक निजी होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के सभी विधायक, सांसद, संगठन जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक में शुजालपुर विधानसभा को लेकर कुछ ऐसा हुआ, जो चर्चा का विषय है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश संगठन पदाधिकारी जो महिला नेत्री हैं, उनकी बात अनसुनी की गई, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए. हालांकि भाजपा के पदाधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया, लेकिन पुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर बबीता परमार व शुजालपुर विधायक इंदरसिंह परमार के बीच किसी बात को लेकर तल्खी देखी गई.

प्रदेश मंत्री महिला नेत्री बबीता परमार की आंखों से आंसू छलक आए. वहीं दूसरी ओर और भी कई मुद्दों पर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बीच भी तल्ख अंदाज में बहसबाजी हुई. हालांकि कोर कमेटी के बैठक की अंदर की बात बाहर आने को लेकर सभी भाजपा नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैठक स्थल के बाहर जो नजारा था, वो कुछ और ही बयां कर रहा था. बैठक में अचानक महिला नेत्री की आंखों से आंसू निकलने का मामला कोर कमेटी में चर्चा का विषय रहा.

पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में झाबुआ प्रदेश का मॉडल जिला बना

झाबुआ, 9 जनवरी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में पेसा कानून (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) के क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने झाबुआ जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पेसा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि झाबुआ सहित प्रदेश के अन्य वनांचल क्षेत्रों में पेसा कानून के अंतर्गत लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जो जनजातीय स्वशासन की भावना को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने पेसा कानून के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को मिले पारंपरिक अधिकारों को धरातल पर उतारने में पेसा जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं मोबिलाइज़र की भूमिका को सराहनीय बताया. सभी विभागों के बीच समन्वय से प्राप्त सकारात्मक परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त की. जिला समन्वयक पेसा एक्ट गौरसिंह कटारा ने बताया कि समीक्षा बैठक में पेसा नियमों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की.

इटली से आए दल ने निगमायुक्त को दिए सुझाव

एमएसडब्ल्यू की प्रोसेसिंग को बनाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड

ग्वालियर, 9 जनवरी. शहर से लीगेसी वेस्ट निपटान एवं फ्रेश वेस्ट निपटान के लिए नगर निगम के आग्रह पर इटली से पाल एसआरएल की टीम ने केदारपुर प्लांट का निरीक्षण किया.

टीम में लुइगिनो पॉलन (इंटरनेशनल सेल्स हेड), एंटोनियो टैजालियो (स्क्रीनिंग डिजाइन एक्सपर्ट), नवीन चीरला (इंडिया सेल्स हेड), निव डिक्टर (प्रोजेक्ट हेड) शामिल थे. टीम के सदस्यों ने निगमायुक्त संघप्रिय के साथ बैठक कर गार्बेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट फील्ड में अपने अनुभव के बारे में बताया. निगमायुक्त ने टीम से केदारपुर प्लांट का दौरा करने और सुधार संबंधी सुझाने देने का अनुरोध किया. बाद में टीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखने और प्रोसेसिंग के तरीके को समझने के लिए केदारपुर प्लांट का दौरा किया. निगमायुक्त संघप्रिय ने निगम मुख्यालय में टीम से भेंट करते हुये उनसे सुझाव आमंत्रित किये. साथ ही विस्तृत चर्चा करते हुये इस संबंध में तकनीकी सलाह दिये जाने की बात कहीं. जिससे केदारपुर प्लांट पर लगे कचरे के पहाड़ों का निष्पादन शीघ्रता से किया जा सकें. टीम के सदस्यों ने उस साइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुई.

सागर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 41 अपराधी जिला बदर

सागर, 9 जनवरी. जिले में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 41 आदतन अपराधियों को विभिन्न अवधि के लिए जिला बदर किया गया है. कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का सर्वोच्च कर्तव्य है और जो भी व्यक्ति बार-बार अपराध कर शांति भंग करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बदर किए गए अपराधियों में राजू यादव पिता खुशीलाल यादव (उम्र 49 वर्ष) निवासी ग्राम झंडीला थाना शाहगढ़ को 10 माह, गब्बर पिता जाफर कुरैशी (37) निवासी अब्दुल हमीद वार्ड खुरई को 5 माह, गौरव उर्फ कृष्णा पिता दीपक रैकवार (19) निवासी प्रताप वार्ड खुरई को 6 माह, सतेन्द्र उर्फ सचिन उर्फ सच्चा पिता हीरालाल अहिरवार (21) निवासी सहोद्रा राय वार्ड खुरई को 6 माह, राहुल पिता कैलाश कुर्मी (28) निवासी ग्राम ओछामल तहसील खुरई को 6 माह, निरंजन पिता फूल सिंह राजपूत (38) निवासी ग्राम सरखड़ी तहसील खुरई को 10 माह, सममर सिंह पिता बलिराम लोधी (31) को 7 माह के लिए जिला बदर किया गया है.

करोड़ों की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त

शासकीय जमीनों के संरक्षण की नीमच में बड़ी कार्यवाही

नीमच 9 जनवरी. कलेक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में शासकीय जमीनों के संरक्षण एवं शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार न.पा.नीमच , राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्यवाही कर नीमच शहर के डाक बंगला रोड़ पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने स्थित खेत नम्बर 10 और बगीचा नम्बर 38 की बहुमूल्य जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, न.पा.के आधिपत्य में लिया गया है और न.पा.के आधिपत्य का सूचना बोर्ड लगाकर अतिक्रमण मुक्त करवाई गई उक्त जमीन पर न.पा.नीमच द्वारा संरक्षित करने के लिए प्रीकास्ट की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया रहा है. शुक्रवार को नीमच शहर में अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही के दौरान जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पराग जैन, न.पा.नीमच की सीएमओ दुर्गा बामनिया, सीएसपी नीमच, तहसीलदार संतोष कुमार एवं संजय मालवीय सहित राजस्व, न.पा.एवं पुलिस अमला मौजूद था. तहसीलदार संजय मालवीय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि नीमच शहर में अतिक्रमण मुक्त करवाई गई.

समीक्षा स्वास्थ्य पैरामीटर पर किए गए कार्य को उप मुख्यमंत्री ने सराहा

स्वास्थ्य सेवाओं में परिणाम परिलक्षित करें

भोपाल 9 जनवरी. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग राजेन्द्र शुक्ल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में अनूपपुर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए कि जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सतत् प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए.

उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य विभाग है. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के वृद्धि के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. समन्वित प्रयास से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य शासन स्तर से जिला चिकित्सालय अनूपपुर के उन्नयन तथा पदों की स्वीकृति एवं पदस्थापना संबंधी कार्य प्रक्रियागत हैं. जिसका लाभ शीघ्र ही जिले को प्राप्त होगा. उन्होंने बैठक में बताया कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में प्रारंभ की गई टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ निचले स्तर तक प्रदान किया जाए. जिससे लोग भी बड़ी संख्या में लाभान्वित हो सकें. उन्होंने स्वास्थ्य अमले को टीम भावना से कार्य करने प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि काम में परिणाम परिलक्षित हो इस दिशा में सभी को मिलजुल कर कार्य करना है.

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य पैरामीटर पर किए गए प्रयासों की सराहना की तथा उन्होंने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्यगत सेचुरेशन के शेष कार्य करने पर जोर दिया. शुक्ल ने समीक्षा बैठक में जिला चिकित्सालय एवं जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के आधारभूत संरचना की जानकारी प्राप्त की. बैठक में आउटसोर्स माध्यम से पैरामेडिकल की समीक्षा की गई.

गंदे पानी की शिकायत पर घर पहुंची कलेक्टर

पानी की जांच की और दिए सख्त निर्देश

ग्वालियर, 9 जनवरी. सीएम हेल्पलाइन पर गंदे पानी की शिकायत सामने आने पर कलेक्टर रूचिका चौहान ने लक्ष्मण तलैया पहुंचकर वस्तुस्थिति जानी. इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता से चर्चा की और उनके घर के अंदर जाकर पानी चैक किया.

निरीक्षण से पूर्व गंदे पानी की समस्या का पीएचई विभाग द्वारा निराकरण कर दिया गया था. निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त संघप्रिय सहित पीएचई विभाग का अमला मौजूद रहा. कलेक्टर रूचिका चौहान ने निर्देश दिए हैं कि गंदे पानी एवं सीवर की समस्या की शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाए, इसमें जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. लक्ष्मण तलैया के नीचे स्कूल के पास गंदा पानी आने की शिकायत सीएम हेल्प लाइन पर की गई थी. शिकायत का पता चलने पर कलेक्टर ने निगम आयुक्त संघ प्रिय के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने डीपीएस स्कूल के आसपास क्षेत्रवासियों से चर्चा की और वस्तुस्थिति को जाना.

इसके बाद उन्होंने लोगों के घरों में पहुंचकर बर्तनों में रखे पानी को चैक किया. निरीक्षण के दौरान पानी साफ मिला. इसके बाद कलेक्टर ने लक्ष्मण तलैया स्थित पानी की टंकी का निरीक्षण किया. पानी की टंकी की सफाई कुछ दिन पूर्व ही की गई थी. कलेक्टर ने पानी की टंकी सफाई की तिथि डालने के निर्देश पीएचई विभाग के अधिकारियों को दिए. साथ ही निर्देष दिए है कि हर छह माह में पानी की टंकी की सफाई की जानी चाहिए.

थाना एवं चौकियों में हो सकता है फेरबदल

सिंगरौली 9 जनवरी. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री सम्पतिया उइके अचानक सिंगरौली आई हैं. जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी. उधर चर्चा है कि मोरवा को नये थाना प्रभारी मिल सकते हैं. साथ ही अन्य थाना व चौकियों में फेरबदल की संभावना है.दरअसल सिंगरौली में हाल ही में कुछ घटनाओं को लेकर भोपाल में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है. मोरवा थाना प्रभारी निरीक्षक यूपी सिंह को अचानक पीएचक्यू भोपाल तबादला के बाद पुलिस महकमे में इन दिनों हलचलें तेज हो गई हैं. मोरवा का थाना प्रभारी कौन होगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं.